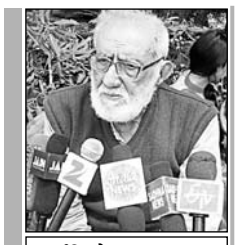

धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र समाजवाद, समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए समर्पित समाचार पत्र

हिंदी साप्ताहिक

जनता रैबार

मसूरी से प्रकाशित समाचार पत्र | वर्ष 02 अंक 20, पृष्ठ : 04 | RNI-UTTHIN/126435/2013 | मूल्य :1/-प्रति, वार्षिक 120 रुपये

रविवार 11 मई 2014 ₹ 1

अंदर

अच्छे दिन आ गए हम सब के – पेज –3

गुजरात मॉडल पर एक नजर पेज –2

1 - 4

अच्छे दिन आने वाले हैं...

16वी लोकसभा के चुनाव परिणाम मीडिया, सभी पार्टियों एवं चुनावी विश्लेशकों के अनुमान के वितरीत रहे हैं। खुद बीजेपी के लिए ये परिणाम आश्चर्यजनक रहे हैं। इस जीत से आरएसएस को संजीवनी मिल गई है। यह ऐसा चुनाव, था जहां हार–जीत का फैसला पहले ही हो चुका था। सट्टेबाजों ने कांग्रेस पर दांव लगाना बंद कर दिया था। अदानी, रिलायंस टाटा जैसे उद्योगपतियों के साथ–साथ पूरे उद्योगजगत के मुख्य चहेते नरेंद्र मोदी थे। यह चुनाव पार्टियों की विचारधारा पर नहीं, बल्कि विशेष के आधार पर लड़ा गया था। इसमें नरेंद्र मोदी ने बाजी मारी और भाजपा को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाई। नरेंद्र मोदी के चुनाव में इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया एवं सोशल साइटों पर करोड़ों रूपये पानी की तरह बहाए गए। अभी तक चुनाव में सबसे ज्यादा सभा एवं हवाई यात्रा (तीन लाख किलोमीटर) नरेंद्र मोदी ने की। एक प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी ने इतिहास से संबंधित गलत जानकारियां दीं, जिसके लिए वे कभी भी खेद प्रकट नहीं करने वाले। जिस तरह हिटलर ने जर्मनी को विश्व का अग्रणी देश बनाने का सपना देखा था, उसी तरह मोदी भारत को विश्वगुरू बनाना चाहते हैं। हिटलर का प्रचार मंत्री गोयब्लस कहना था कि एक बात को इतनी बार बोलो कि उसको लोग सही मानने लगें। उस तर्ज पर गुजरात के विकास मॉडल का प्रचार किया गया। नारे दिए गए "अच्छे दिन आने वाले हैं।" अब ये अच्छे दिन किस तरह के होंगे, नमो–नमो ही जाने।

अच्छे दिन

सवाल यह है कि अच्छे दिन किसके आने वाले हैं ? क्या उन किसानों के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं, जो सरकारी नीतियों के कारण आत्महत्या करने और आधे पेट खाने को मजबूर हैं ? क्या फैक्ट्रियों में हाड़–तोड़ मेहनत करने वाले मजदर, जो 10 से 12 घंटे और कभी इससे भी ज्यादा समय काम करके कबूतरखाने जैसे बने कमरों, झोपड़ियों में रहते हैं और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर गांव वापस चले जाते हैं, के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या उन महिलाओं के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, जो पेट की आग बुझाने के लिए अपने शरीर को बेचती हैं या चंद पैसे के लिए किराए की कोख का काम करती हैं, अपने बच्चों तक को बेचने, उन्हें मारने पर मजबूर हो जाती हैं, जलील–अपमानित होने पर आत्महत्या जैसे कदम उठाती हैं।

अहमदाबार के बुहूपुरा में रहने वाली 65 साल की नियाज बीबी के दो मंजिला कमान को दंगे में जला दिया गया था। अब वो किराए के एक कमरे में पांच लोगों के साथ गुजारा करती हैं। वो बताती हैं कि उनको किराए पर दुकान इसलिए नहीं मिलती क्योंकि लोगों को डर है कि इनकी दुकान जलाई जाएगी तो पास में दूसरे हिंदु दुकानदारों की दुकानें भी जल सकती हैं। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर हमा बताती हैं कि उनके इलाके में सप्लाई का पानी कई–कई दिन नहीं आता है। जबकि जुहूपूरा के दूसरी तरफ पानी जाता है। क्या निजाज बीबी और हुमा के भी अच्छे दिन आने वाले हैं ? क्या हरिणा के उन दलित परिवारों के अच्छे दिन आने वाले हैं, जो अपनी बच्चियों के साथ हुए बलात्कार के मामले में इंसाफ मांगने के लिए एक माह से अधिक समय से जंतर–मंतर पर बैठे हैं? क्या उत्तराखंड के दलित परिवारों के भी अच्छे दिन आने वाले जिन्हें दबंगों ने गांव से निकालकर जमीने हथिया ली? जौरसार–बाबर जनजाति क्षेत्र के जनजाति सवर्ण जातियों द्वारा दलितों को आज भी मंदिर का आंगन तक छूने नहीं दिया जाता, क्या इनके भी अच्छे दिन आने वाले है? बेरोजगारी की वजह से पहाड़ों से पलायन कर रहे नौजवानों के अच्छे दिन आएंगे क्या ? क्या निप्पौन, गर्जियानी, मारूति के मजदूरों, जो सालों से जेल में बंद हैं ओर जिनकी परिवारिक हालत खराब होती जा रही है, के भी अच्छे दिन जाएंगे। या फिर अच्छे दिन उन पूंजीपतियों के आने वाले हैं, जिनके शेयर के दाम 12 मई के एक्जिट पोल दिखाने के बाद लगातार बढ़ते गए? 13 सितंबर को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के उम्मीदावार घोषित होने के बाद से ही अरविंद लिमिलटेड, कैडिला, पीपावावा, अदानी जैसे गुजरात स्थित कंपनियों के शेयर लगातार बढ़ने लगे हैं। मोदी इफेक्ट ही था कि अदानी की पूंजी मध्य फरवरी से 9 मार्च तक 25 दिनों

में 20000 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी हो गई। अदानी ने 16 मई को चुनाव रिजल्ट के ही दिन 5500 करोड़ रूपये के धमारा पोर्ट का अधिग्रहण करने के लिए टाटा के साथ समझौता किया। निश्चित ही अच्छे दिन इन पूंजीपतियों के आने वाले हैं। अच्छे दिन रामदेव जैसे अकूत संपदा के मालिक बाबाओं के आने वाले हैं, जिन्होंने कुछ ही वर्शों में 1500 करोड़ रूपये का साम्राज्य खड़ा कर दिया है, जमीने कब्जा ली और अरूण जेटली सरीखे चाटुकार अब उनकी तुलता महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण से कर रहे हैं।

उद्योग जगत की आशाएं

गौतम अदानी ने कहा कि देश को ऐसी सरकार की जरूरत है, जो राजनीतिक रूप से व्यावहारिक आर्थिक समझदारी वाले फैसले कर सकें और इन पर रूख साफ कर सकें। अपने प्रचार अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने ऐसी सरकार पर जोर दिया, जो फैसले करने वाली हो और मजबूत प्रशासन मुहैया कराने पर केंद्रित हो। इसका नीति निर्माण और उन्हें लागू करने पर सकारात्मक असर पड़ेगा और नीतियों को लागू करने में पारदर्शिता आएगी। इससे परियोजनाओं को लागू करने में तेजी आएगी। साथ ही इससे निवेश में भी तेजी आएगी। डॉयशे बैंक के सह सीईओ गुनीत चड्ढ़ा का कहना है कि नई सरकार का सबसे बड़ा काम भारत के कॉरपोरेट जगत का विष्वास बहाल करना है।

GANNON DUNKERLEY & CO.LTD.

(An ISO 9001-2000 Company)

REGISTERED OFFICE

NEW EXCELSIOR BUILDING, 3RD FLOOR, A.K. NAYAK MARG
FORT, MUMBAI-400001

TEL:91-22-22051231, FAX-91-22-22051232
Website : gannondunkerley.com
E-mail : gdho1@mtnl.net.in

GANNONS ARE SPECIALISTS IN INDUSTRIAL STRUCTURES, ROADS,BRIDGES (RCC AND PRESTRESSED CONCRCETE), RAILWAY TRACKS, THERMAL POWER, FERTILIZER, CHEMICAL, PAPER AND CEMENT PLANTS, WATER & WASTE WATER TREATMENT PLANTS, PILING FOUNDATION & FOUNDATION ENGINEERIG.

GANNONS ARE ALSO PIONEERS IN MATERIAL HANDELING WORKS, MANUFACTURE OF PRESTRESSED CONCRETE SLEEPERS, ERECTION OF MECHANICAL EQUIPMENTS & PIPING AND SUPPLY OF TEXTILE MACHINERY AND LIGHT ENGINEERING ITEMS

OFFICES AT :

AHMEDABAD - CHENNAI - COIMBATORE - HYDERABAD - KOLKATA
MUMBAI - NEW DELHI

वाईएमसी की बैठक 22 जून को

कांडीखाल। युसुफ मेहरअली सेंटर की मैनेजिंग कमेटी की बैठक आगामी 22 जून को उत्तराखंड कार्यालय कांडीखाल में होगी। इस बैठक में आपदा के एक साल में अब तक सेंटर की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी, साथ ही भावी रणनीति भी तैयार की जाएगी। सेंटर ने थत्युड़ क्षेत्र के 10 गांवों में राहत और पुनर्वास का काम शुरू किया है। जिसे संस्था आगे बढ़ाना चाहती है। ताकि, प्रभावित ग्रामीणों का जीवन दोबारा पटरी पर लाया जा सके। सेंटर की आगामी बैठक में संस्था के निदेशक और वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजवादी चिंतक डा. जीजी पारिख, भारत सरकार खाद्यी कमीशन के पूर्व चेयरमैन और संस्था के सचिव हरीश शाह, डा. सुनीलम, मंजू मोहन आदि शिरकत करेंगे।

निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा ग्रामीणों को दी राहत

मसूरी। युसुफ मेहरअली सेंटर के तत्वाधान में थत्युड़ क्षेत्र के आपदा प्रभावितों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप के लिए आरोग्य सेना पुना की ओर से भी कुछ दवा उपलब्ध कराई गई थी। 9 मई को कांडीखाल में भी एक मेडिकल कैंप लगाया गया था। इन षिविरों में 200 से ज्यादा महिला, बच्चे और बुजुर्गों को दवा वितरीत की गई।

मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए इन दिनों लोग बीमार हो रहे हैं। खासकर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोग मुष्किल में हैं। इससे लोगों के अच्छे इलाज के लिए मसूरी, दून अथवा विकासनगर का रूख करना पड़ रहा है। युसुफ मेहरअली सेंटर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगातार अच्छी दवाएं वितरित की। डा. रमेश लेखवार और पूरण सिंह कंडारी ने मरीजों को दवा वितरित की। निशुल्क चेकअप किया गया और दवा बांटी। कैंप सुबह से दोपहर तक चले। मेडिकल कैंप के लिए आरोग्य सेना पुना ने भी कुछ दवा उपलब्ध कराई थी।

इससे पहले प्राकृतिक आपदा के दौरान भी वाईएमसी और आरोग्य सेना ने देषभर से जुटे जानेमाने चिकित्सकों के साथ उत्तरकाषी और टिहरी जनपद के आपदा प्रभावित गांवों में पहुंचकर कई मेडिकल कैंपों के जरिए हजारों लोगों का निशुल्क इलाज मुहैया कराया था। थत्युड़ के कई आपदा प्रभावित गांवों में पहुंचकर चिकित्साकों ने लोगों का इलाज किया था। मेडिकल कैंपों की क्षेत्रवासियों ने सराहना की।

कांडीखाल में भूसा स्टोर का निर्माण शुरू

कांडीखाल। युसुफ मेहरअली सेंटर ने गौशाला निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए पांच सेंटरों पर गौशालाएं खोलकर उसमें गाय रखी जाएंगे। इसके लिए कांडीखाल स्थित वाईएमसी राज्य कार्यालय के पास भूसा स्टोर तैयार किया जा रहा है, ताकि विकासनगर, देहरादून आदि शहरों से भूसा लाकर यहां स्टोर किया जा सके।

पहाड़ों में भूसे की कमी के चलते लोग इसके लिए शहरों पर ही निर्भर रहते हैं। जबकि जर्सी, मिक्स जर्सी गायों को भूसे की जरूरत होती है। इससे पहाड़ों में इन गायों को पालना मुश्किल हो जाता है, जबकि चारा–पत्ती पर पलने वाली पहाड़ी गाय दुग्ध कम देती है। ऐसे में, वाईएमसी ने कांडीखाल में गौशाला के साथ ही भूसा स्टोर खोलने का तय किया है। इससे जहां संस्थान की गौशालाओं को भूसा सप्लाई किया जा सकेगा, वहीं जरूरत पड़ने पर आपदा प्रभावित जौनपुर क्षेत्र के पशु पालकों को भी उचित दाम पर भूसा उपलब्ध कराया जा सकता है। संस्था के उत्तराखंड संयोजक जबर सिंह वर्मा ने बताया कि स्थानीय प्रभावितों को भूसा स्टोर का फायदा हो, इसके लिए संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत की जा रही है।

गुजरात मॉडल पर एक निगाह

संदीप पांडेय

राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात चर्चा में आ गया है। लोकसभा चुनाव में जैसे "भाजपा की सरकार" की बजाय "मोदी सरकार" का नारा जोर शोर से चला वैसे ही "मोदी का गुजरात" कहने की भी भरपूर कोशिशें हुईं। मानों गुजरात यानी मोदी हो। गुजरात के प्रसिद्ध विकास मॉडल ने लोगों का ध्यान आकर्शित किया है। ऐसे में इसकी जांच पड़ताल होना भी स्वाभाविक है।

एक चीज जिसकी तरफ कम लोगों का ध्यान गया है, वह है गुजरात में जीने का खर्च। यह काफी ज्यादा है। यह सिर्फ गुजरात की संपन्नता की वजह से नहीं है। दूसरे बड़े शहरों जैसे मुंबई या कलकत्ता से तुलना करें तो अहमदाबाद में रहना काफी खर्चीला है। बाजार में एक कप चाय यहां 10 से 12 रूपये में मिलती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम इंसान के लिए यहां अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कितना दुश्कर होगा। खाद्य सामग्रियों की कीमत तो यहां अन्य जगहों से अधिक ही है। यहां बाल कटवाने के लिए कम से कम 50 रूपये तो लगेंगे ही। एक मध्यम वर्गीय परिवार के रहने के लिए लैट कर किराया लगभग 10 हजार रूपये प्रति माह होगा और बिजली का बिल अलग से न्यूनतम 2 हजार रूपये प्रति माह होगा। यह तब है जबकि तेजी से अहमदाबाद में सभी जगह बहुमंजिला इमारतें दिनरात खड़ी होती जा रही हैं। यदि हम भारत के अन्य भागों से तुलना करें तो कह सकते हैं कि गुजरात में रहना महंगा है। इसके दो निहितार्थ हैं। एक तो यहां उपभोक्ता वर्ग की आय अधिक होगी इस आय के मुताबिक ही चीजों के दाम ज्यादा हो गए हैं, किंतु गरीब वर्ग को इस मूल्य वृद्धि की ज्यादा मार झेलनी पड़ती है। इसका यह भी परिणाम है कि अमीर और गरीब के बीच आय में अंतर गुजरात में देश के अन्य हिस्सों से ज्यादा है। डा. मनमो. हन सिंह और मोंटेक सिंह अहल. ूवालिया के लिए यह स्थिति शायद उनके आर्थिक विकास के मॉडल की सफलता का एक मानक होगी।

यदि गरीबों की स्थिति पर नजर डाली जाए तो देश के अन्य भागों और गुजरात में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अहमदाबार रेलवे स्टेषन पर अच्छे–खासे कपड़े पहने लोग भीख मांगते मिल जाएंगे। रेलवे के डिब्बों में उसी तरह बच्चे सफाई करते मिलेंगे। झुग्गी झोंपड़ियों की स्थिति काफी बुरी है। अच्छे आवास, पानी और शौचालयों का अभाव है। गटर साफ करते हुए औरत दो सौ लोगों की सालाना मृत्यु हो जाती है। दैनिक मजदूर, न्यूनतम मजदूरी से वंचित है और श्रम कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुजरात में आदिवासियों की स्थिति विशेषकर बद से बदतर है। कुपोषण की समस्या इनके बच्चों में ज्यादा है। गुजरात में वैसे तो शराबबंदी है, किंतु रूपये 40 हजार मासिक के भुगतान पर पुलिस के संरक्षण में विदेशी शराब का धंधा आसानी से चलाया जा सकता है। इनका संचालन आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग करते हैं। गुजरात पुलिस की भूमिका पर कुछ और चर्चा भी जरूरी हैं। सूरत में एक परिवार को सात वर्श पहले बांग्लादेषी बता पति–पत्नी और नौ में से छह बच्चों को जेल में डाल दिया गया था। पति–पत्नी अभी भी जेल में ही हैं।

इस परिवार के पास राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, बिजली का बिल आदि सबकुछ है। नौ बच्चों की पैदाइश, जिसमें सबसे बड़ी 26 साल की लड़की है। परिवार का मुखिया एक दरगाह से जुड़ा था। सवाल यह है कि यदि परिवार दोशी है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही हुई जिन्होंने इस परिवार के राशन कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक बनवाए। पासपोर्ट बनाने में तो पुलिस, इंटेलिजेंस की स्वीकृति आवष्यक है।

संपादकीय

जनता को नहीं है सड़क पर संघर्ष करने वाले नेताओं की जरूरत

जो लोग धूप में अपने घरां से नहीं निकल सकते, अपने भविष्य और अपनी सुख सुविधाओं के अलावा और कुछ जिन्हें दिखाई नहीं देता, हर बात जिनकी मैं से शुरू होती है और मैं पर ही खत्म होती है वो बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति को खारिज कर देते हैं।

गरीबों के बीच दान बांटना, वृद्धा आश्रम में जाकर लोगों की सेवा करना ऐसी तमाम बाते अच्छे इंसान की पहचान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिनके पास कुछ नहीं है, उनको हमेशा आप दान ही देते रहेंगे। सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार उनका है और उनके हक की लड़ाई उनके साथ कई लोग लड़ रहे हैं। गलती इंसान से ही होती है, क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? परिवार के अंदर कई बार कई निर्णय का अच्छा आता है, कई बार गलत भी। आप क्या बार– बार उस निर्णय के लिए उनको कोसते हैं। गलती करने वाले सदस्य को आप घर से निकाल नहीं फैंकने, बल्कि उनको समझाते हैं। बड़ा बुरा लग रहा है कि इन्ही केजरीवाल को 8 दिसंबर को लोग भगवान की तरह पूज रहे थे और अचानक सभी के लिए वो बुरे हो गए। मेरी सलाह है कि केजरीवालजी आप भी इन लोगों की तरह कहीं नौकरी कीजिये। आराम से जिंदगी जिए और थोड़ा बहुत दान कर दीजिएगा क्योंकि अब लोगों को नेता सिर्फ लच्छेदार–बड़बोले भाशण देते हुए अच्छे लगते हैं ना की सड़क पर संघर्ष करते हुए।

गुजरात मॉडल पर एक निगाह .....

ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात में देश के अन्य हिस्सों से शायद ज्यादा फर्जी मामलों में लोगों को फंसाने का काम होता है। इन मामलों में बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता तो अब जगजाहिर है। मुख्यमंत्री के खास अमित शाह जिस मामले में आरोपी हैं उस सोहराबुद्दीन का संबंध अवैध धंधों में से था। सो. हराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। इस मामले में कुछ बड़े पुलिस अधिकारी जेल में हैं।

गुजरात के वर्तमान सीएम और देश के भावी प्रधानमंत्री ने निजीकरण को खूब बढ़ावा दिया। अदानी ग्रुप ने सीएनजी आपूर्ति और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में लगभग एकाधिकार कायम किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कंपनी का मालिक सीएम के खासमखास हैं। इस कंपनी को मुंद्रा में एक निजी बंदरगाह चलाने की भी अनुमति मिली हुई है। इस कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य व लोगों के हितों को कई बार ताक पर रखा जा चुका है।

गुजरात में संपन्न वर्ग की सुविधाओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है और शेष वर्गों के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। मध्य वर्गीय गुजराती समाज भी, जिसमें पैसे की सोच प्रधान है, उनसे खुष है क्योंकि मुख्यमंत्री उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखते हैं। उनकी नीतियों का समाज में कम भाग्यशाली तबके के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। उसे इससे भी मतलब नहीं कि गुजरात के विकास के मॉडल के पीछे राजनेताओं, अधिकारियों, अपराधियों, निजी कंपनियों और ठेकेदारों का एक मजबूत गठजोड़ है।

अच्छे दिन आने वाले हैं.....

इसके लिए बेहतरीन तरीका पुरानी परियोजनाओं की राह में आ रही बाधा दूर करने के लिए निश्चित कार्रवाई करना होगा। सरकार और नौकरशाही के बीच तालमेल से फैसले किए जाने की जरूरत है। ऐसे में फैसलों से विश्वास बहाल किया जा सकता है। एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन रमेश शाह का कहना है कि नई सरकार के आने से देश में विश्वास का माहौल सुधरने की उम्मीद है।

इससे पूंजी बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पिछले दो दशकों से भारतीय पूंजी बाजार का नाटकीय तरीके से विकास हुआ है, लेकिन इसे अभी लंबा सफर तय करना है। निवेशक और उद्योग पूंजी बाजार के अहम घटक हैं। अगर इनसे जुड़े मुद्दों का हल होगा, तो इससे एक मजबूत पूंजी बाजार के निर्माण में मदद मिलेगी।

पीरामल समूह के चेयरमैन अजय पीरामल भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव चाहते हैं। हमें तत्काल ही खान और ढांचागत क्षेत्र में सुधार लाना चाहिए और अप्रत्यक्ष विदेश निवेश को और उदार बनाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर इसके लिए जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ बैंकों को भी पूंजी देने की जरूरत है, ताकि उन्हें कारोबार आगे बढ़ाने और उधार देने में कोई दिक्कत नहीं आए और यह भी तत्काल किए जाने की जरूरत है। विनिर्माण और ढांचागत क्षेत्र को भी मजबूती देने की जरूरत है, जिसके लिए पिछले साल पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक को पलटना होगा (श्रोत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 17 मई 2014)

इस बात को बल भजपा के वरिश्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के टीवी चैनल के वार्तालाप से मिल जाता है कि 200–250 कंपनियों की फाइलें पर्यावरण विभाग के क्लियरेंस के लिए ऑफिसों में पड़ी हैं। उनका क्लियरेंस नहीं दिया गया है।

इसका यह मतलब है कि जनता के लगातार संघर्श के कारण जनदबाव में जो क्लियरेंस नहीं मिला है, वह अब मिल जाएगा। अदानी ग्रुप के मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में चल रहे जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ डा. सुनीलम, एडवोकेट आराधना भार्गव, मेधा पाटकर जैसे लोगों का संघर्श अब कुचला जाएगा। इसी बात से पूंजीपतियों के समूह काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

विकास का जन आंदोलन

मोदी ने अपनी विक्टरी रैली में बोलते हुए कहा कि वे विकास को एक जन आंदोलन बनाना चाहते हैं, जैसा कि गांधीजी ने आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया था। कोई पढ़ता था, कोई चरखा काटता था, वह भी आजादी की लड़ाई थी। उसी तरह हम विकास को जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। वे जिस तरह से गुजरात में विकास का आंदोलन बना कर नर्मदा बचाओं आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर पर हमला करवाए, क्या उसी तरह कारपोरेट जगत के विकास की खिलाफत कर रहे लोगों पर भी हमला करवाना चाहते हैं? विकास के जन आंदोलन का काम आरएसएस के हाथों में सौंप दिया जाएगा?

मोदी के आने से साफ हो गया कि उदारीकरण की नीतियों को तेजी से लागू किया जाएगा। जिसके लिए एक फासीवादी व्यक्ति की जरूरत है, जो लोगों की आवाज को कुचल सकें और उद्योगपतियों के लिए हर सुविधा दे सकें।

प्रत्यक्ष करों में छूट दी जाएगी और देश की जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ा दिया जाएगा, ताकि वे दिन चौगुनी–रात आठ गुनी तरक्की कर सकें। आम जनता को उसी तरह सपना दिखाते रहो, जैसे धर्म में दिखाया जाता है कि जन्म में अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। इसी तर्ज पर अच्छे दिन का सपना दिखाया जाता रहेगा।

अच्छे दिन आ गए हम सबके ...

गुड्डी

बहुत सारे लोग मुझे 16 मई के बाद इसलिए माना मार रहे हैं कि मैने आप पार्टी की उम्मीदवार मेधा पाटकरजी के लिए दो महीने काम किया। आप पार्टी को पंजाब के अलावा कहीं भी लोकसभा सीट नहीं मिली। लोगों की नजर में अरविंद केजरीवाल, योगजेंद्र यादव, मेधा पाटकर सब बेकार हैं, क्योंकिअब की बार मोदी सरकार है।

साथियों मैने पहले भी कहा कि मैं आप आदमी पार्टी की सदस्य नहीं हूं, ना ही उनके खिलाफ हूं। जो लोग मेधा पाटकर जी को जानते हैं, वो यह भी जानते होंगे कि वो किसी भी पार्टी से उपर है, उनके लिए काम करना हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। जनता का फैसला उनके हक में नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं कि उनके 38 वर्शों के सराहनीय काम को नकार दिया जाए। हमने लोगों के लिए पहले भी काम किया है और आगे भी करते रहेंगे।

परसों की बात है मुलुंड पूर्व में अंबेडकर नगर में 130 परिवारों के घर तोड़ दिए गए। लोग फूटपाथ पर हैं।, सिर पर छप्पर नहीं है लेकिन हम लड़ रहे हैं। कहते हैं बस्ती गैर कानूनी थी, जबकि बस्ती के लोग न्यायालय में थे और 8 दिन बाद ही इसका फैसला आने वाला था। लेकिन जिसने जमीन खरीदी उसने प्रषासन और सत्ता में आई नई सरकार का सहारा लेकर लोगों को सड़क पर लाया। तो अब क्या कहें, इस 130 परिव. रों के अच्छे दिन आ गए हैं...। इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर बरसों से बसया आपका घर आपके सामने ही कोई बेहरमी से जमींदोज कर दें, और आपके पास कोई दूसरा छप्पर

भी न हो इस कड़कड़ाती धूप में। आने वाले समय बरसात का हो तो आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे सिर छुपाने।

चुनावों में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह कभी बीजेपी के लोंगो को कहते सुना था, लेकिन जीत का इतना अभिमान तो ठीक नहीं है। पिछले 10 वर्शों के दो लोकसभा चुनाव में बीज. `पी भी हारी थी, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। चुनाव में मोदी की लहर काम कर गयी। यह समझने वाले लेाग यह जान ले कि मोदी की लहर बनाने के लिए इस कॉरपोरेट जगत ने आपका खून चूसकर पैसा बनाया और वो प्रचार प्रचार में लगाने के लिए मोदी को दिया। अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए क्या मोदी ने सिर्फ 70 लाख खर्च किया होगा अपने चुनाव प्रचार में ? कांग्रेस हो या बीजेपी सभी दलों के उम्मीदवार जो तीत के इस समय लोकसभा में गए हैं सबके खर्चे 70 लाख से ज्यादा हैं। करोड़ों में। लेकिन..... आप भी कहेंगे कि जो कह रहे हैं उसे साबित कीजिए। नहीं साबित कर सके तो मानहानी का मुकदमा आदि–आदि। .... जमानत के लिए मुचलका भर दिया तो पुरे देष में चिल्लाया जाएगा, देखो जमानत पर बाहर हैं। मुचलका नहीं भरा तो देखो जेल की हवा खाने के साथ ही कहा जाएगा ...देखो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुचलका ना भरने की पुरानी परंपरा आंदोलन की है। न्यायालय के अंदर हम सभी यही कहते हैं कि हम सही हैं। आप हमें जेल भेजना है तो भेज दो पर जमानत पर बाहर नहीं आएंगे।

उत्तर प्रदेष और बिहार के हजारों लेाग जो रोज मुंबई रोजगार की तलाष में आते हैं , वो बहुसंख्यक इन बस्तियों में रहते हैं इन्हीं बस्तियों को तोड़ा जा रहा है क्या षिवसेना और मनसे जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है वो अब इनके खिलाफ नहीं बालेंगे? क्रूा वे अपनी इस सरकार से इन बस्तियों के रहवासियों को पुनर्वास दिवाएंगे? पूरा चुनाव विकास के मुद्दे लड़ा गया सेा उम्मीद की जाए की अब उत्तर प्रदेष और बिहार में इतने रोजगार निर्माण किए जाएंगे कि लोग मुंबई का रूख नहीं करेंगे। लोग सूरत और अहमदाबार नहीं जाएंगे? सरकारी स्कूल इतने अच्छे होंगे कि हम हजारों की फीस देकर अपने बच्चे को निजी स्कूल में नहीं भेजेंगे? सरकारी अस्पताल सारी सुविधा संपन्न होंगे? सरकारी कर्मचारी रिष्वत लिए बगैर हमारा काम करेंगे। गुजरात की तरह पुरे देष में षराब पर पाबंदी होगी?

मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी अब यह लिखकर दे दे कि इस देष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हम क्या बोलें, कब बोलें और कहां बोलें? पता नहीं देष की राजनीति को क्या हो गया है। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने 60 महीने मांगे थे, देष की तस्वीर बदलने के लिए, जनता ने उन्हें यह मौका दे दिया है, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार देकर। एक सरकार मुंबई को संघाई बनाने पर आमदा थी और अब दूसरी तस्वीर बदलने पर। होता क्या है हम और आप तो देखेंगे ही।

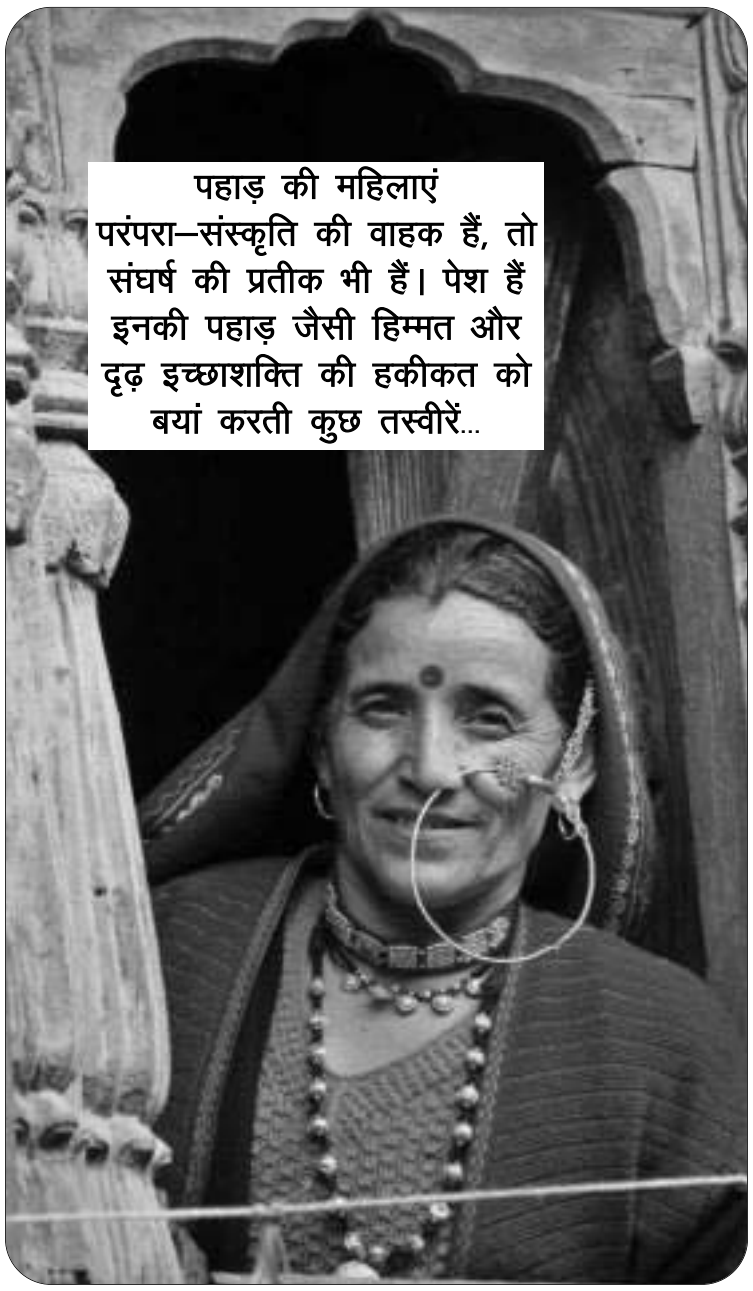

स्वामी मुद्रक और प्रकाशक कलावती द्वारा शैलवाणी प्रिंटर्स, 1/12 न्यू चुक्खूवाला, देहरादून से मुद्रित तथा लेन एडन आउट हाउस, डिक रोड, कंपनीबाग, मसूरी, जिला देहरादून, उत्तराखंड से प्रकाशित।

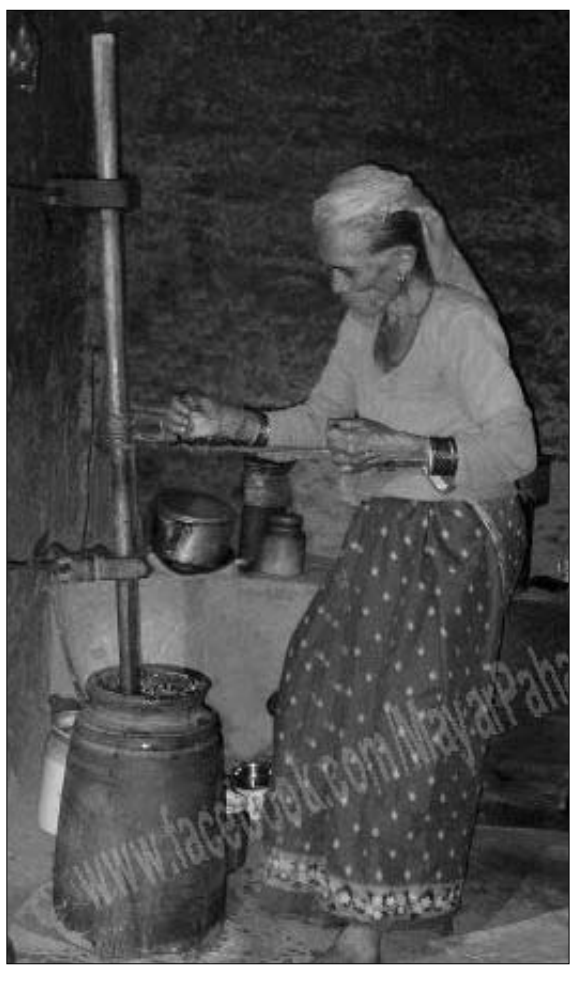

संपादक
जबर सिंह वर्मा
फोन. 9927145123
9411513894

Email-
jantaraibar@gmail.com
jabars9@gmail.com

(समाचार संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र मसूरी (देहरादून) ही मान्य होगा)

संरक्षक मंडल
डा. जीजी पारिख
सुश्री मेधा पाटकर
श्री विजय प्रताप
श्री चंद्रसिंह

संपादक मंडल
डा. सुनीलम
प्रो. सुभाष वारे
विमल भाई
गुड्डी
सुरेश भाई
प्रेम पंचोली
राजेश कुमार, विरेंद्र लाल

विशेष सहयोग :
युसुफ मेहरअली युवा बिरादरी